

प्रेषक,

एम०एच० खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 :

देहरादून: दिनांक-29 मार्च, 2013

विषय:- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के उप मिशन UIDSSMT के अन्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के उप मिशन UIDSSMT के अन्तर्गत रु. 6173.25 लाख लागत की मसूरी सीवरेज योजना भारत सरकार से स्वीकृत हुयी है, जिसमें रु. 4938.60 लाख केन्द्रांश एवं रु. 1234.65 लाख राज्यांश निर्धारित है, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या: भा०स० 77 / IV- श०वि०-09-22 (एन०यू०आर०एम०)०८, दिनांक 26.03.2009 के द्वारा रु. 2469.30 लाख केन्द्रांश एवं रु. 617.33 लाख राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल रु. 3086.63 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(3)/PFI/2012-1480, दिनांक 28-02-2013 द्वारा उक्त योजना हेतु स्वीकृत केन्द्रांश रु० 2469.30 लाख तथा उक्त केन्द्रांश के सापेक्ष निर्धारित राज्यांश रु० 617.32 लाख सहित रु० 3086.62 लाख (रुपये तीस करोड़ छियासी लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
3. JnNURM योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
5. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
6. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का

कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

7. आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
8. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
9. कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।
10. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13, लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-04-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण (यू०आई०डी०एस०एम०टी०)- 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०- 1136/xxvii(2)/2012, दिनांक- 29 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं०-183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार क्रमशः अलॉटमेन्ट आई०डी०- S1303130789 के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम०एच० खान)
सचिव।

सं० 456(1)/IV-श०वि०-2013, तददिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी
11. अधिशासी अभियन्ता, दून डिवीजन, उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)

अनु सचिव।